माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

केन्द्रीय छात्रवृत्ति फ्रेश 2018 व 2015 से 2017 के नवीनीकरण हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, नई दिल्ली की केन्द्रीय छात्रवृत्ति 2018 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। राजस्थान बोर्ड के ऐसे परीक्षार्थी जो **Top** 20 पर्सेंटाइल की श्रेणी में आते हैं, वे 31.10.2018 तक रात्रि 12:00 बजे तक ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान बोर्ड द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक परीक्षा 2018 में कला, वाणिज्य व विज्ञान संकाय से परीक्षा उत्तीर्ण कर कॉलेज/विश्वविद्यालय में नियमित अध्ययन कर रहे विद्यार्थी, आवेदन के लिए पात्र हैं। विद्यार्थियों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के **National e - Scholarship Portal** के लिए **www. scholarships.gov.in** पर छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाईन आवेदन करना होगा। **Top** 20 पर्सेंटाइल की गणना राजस्थान बोर्ड द्वारा जारी संवीक्षा पूर्व के परिणाम पर आधारित है। सभी दिव्यांग विद्यार्थी भी इसमें आवेदन कर सकते हैं।

छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करना ही चयन का आधार नहीं होगा। छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थियों का चयन एमएचआरडी के निर्धारित मापदंड अनुसार होगा।

केन्द्रीय छात्रवृत्ति 2017 के लिए चयनित विद्यार्थी प्रथम नवीनीकरण, 2016 के लिए चयनित विद्यार्थी द्वितीय नवीनीकरण व 2015 के लिए चयनित विद्यार्थी तृतीय नवीनीकरण हेतु उपरोक्त पोर्टल पर आवेदन करें। वर्ष 2017, वर्ष 2016, व, वर्ष 2015 नवीनीकरणों के आवेदन हेतु विद्यार्थी के अध्ययनरत पाठ्यक्रम में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक हो या समकक्ष ग्रेड अथवा यदि समेस्टर प्रणाली है तो दोनों समेस्टर के अंकों का औसत न्यूनतम 50 प्रतिशत हो, आवेदक की उपस्थिति न्यूनतम 75 प्रतिशत हो, आवेदन के पात्र हैं।

ऑनलाइन आवेदन करने संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु हैल्पलाइन नं. 0120-6619540 पर सम्पर्क किया जा सकता है। **नोटः- छात्रवृत्ति के नवीनीकरण हेतु न्यूनतम 50% का मापदंड एमएचआरडी द्वारा शैक्षिक सत्र 2018-19 से ही शुरू किया गया है।**

सचिव

Education News Group

बिजली न होने के कारण पेड़ो के नीचे लगानी पड़ रही है कक्षाएं

आजादी के 72 साल बाद भी 390 सरकारी स्कूलों में नहीं पहुंची बिजली

नवज्योति एक्सक्लूसिव

कागजी खानापूर्ति बन रहे है वार्षिक प्लान

नवज्योति/कोटा

आजादी के 72 साल बाद भी सैकड़ों सरकारी स्कूल बिजली जैसी सामान्य सुविधा से दूर है। अच्छे प्रकृति की कगर में पहुंचने वाली रोशनी में पढ़ने को मजबूर है। ऐसे हालात कोटा जिले के है। जिले में इतने सालों बाद भी 390 सरकारी प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों तक बिजली नहीं पहुंच पाई है। सालों बाद भीइन स्कूलों में बिजली नहीं पहुंचना हैरान तो करता है, वहीं बिजली के अभाव में बच्चों को खासी दिक्कत होती है। कोटा में किशोरपुरा स्थित स्कूल में बिजली नहीं होने के कारण पेड़ों की छांव में ही पढ़ाई हो रही है। सर्व शिक्षा अभियान और स्थानीय राजनेता हर साल इन स्कूल में बिजली पहुंचाने का दावा करते है। जिले में कुछ स्कूल तो ऐसे भी है, जहां पर पिछले कई सालों से न तो अधिकारी पहुंचे है नहीं कोई जनप्रतिनिधि। स्कूल में बिजली नहीं होने का खामियाजा सबसे ज्यादा बच्चों को भुगतना पड़ता ही है। साथ ही शिक्षक भी इससे परेशान है। हालांकि, शिक्षकों और संस्थाप्रधानों की ओर से इसके लिए जिला अधिकारियों को बार-बार सूचना दी जाती है। उसके बाद भी होता कुछ नहीं है।

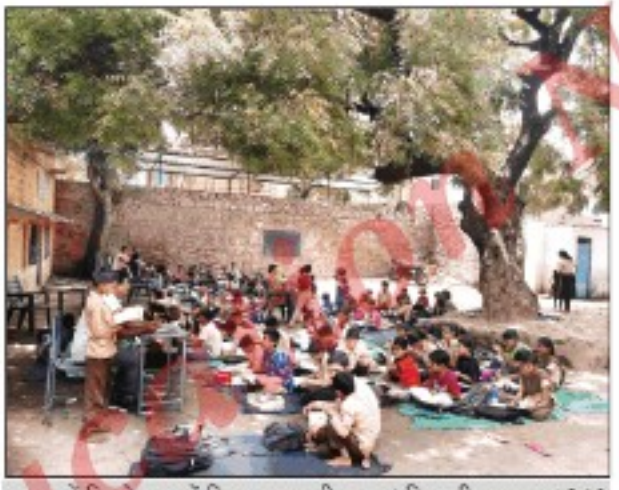

शहर में किशोरपुरा में स्थित सरकारी स्कूल। जिसकी स्थापना 1946 में हो गई थी। यहां आज तक भी बिजली नही पहुंची है। - एचजी

16 स्कूलों में ही हुआ विद्युतीकरण

प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत वैसे तो 735 स्कूल है। इसमें पिछले सत्र में जिला विकास योजना के माध्यम से 16 स्कूलों में ही विद्युतीकरण कार्य किया गया है। इसने इस योजना से 15 हजार प्रति स्कूल से रुपए खर्च किए गए थे। जबकि, हर साल सैकड़ों स्कूलों की ओर से विद्युतीकरण की डिमांड आती है। उसमें से गान मात्र के स्कूलों में विद्युतीकरण का कार्य किया जाता है। ऐसे में सरकारी स्कूल में शिक्षा प्रणाली की पोल खुल रही है। इसी कारण प्राथमिक शिक्षा में साल दर साल गिरावट आती जा रही है।

120 स्कूलों को किया है प्लान में शामिल

जिले में 390 स्कूल अभी भी अंधेरे में है। इसमें सर्व शिक्षा अभियान की ओर से 120 स्कूलों में बिजली कनेक्शन करवाने के लिए वार्षिक प्लान तैयार कर भेज दिया है। लेकिन, 120 स्कूलों में से कितने स्कूल के लिए बजट मिलता है। पिछली बार भी मांग के अनुरूप बजट नहीं मिलने के कारण केवल 16 स्कूलों में विद्युतीकरण का कार्य हो पाया था।

ऊंट के मुंह में जीरा साबित होता है बजट

शिक्षा विभाग की ओर से स्कूलों के विकास के लिए भेजा जाने वाला बजट ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है। शिक्षा विभाग की ओर से एक स्कूल के लिए 5000 का बजट दिया जाता है। इसमें साल भर में स्कूल की मरम्मत, स्कूल का रंग-रोगन, शौचालय और पेयजल समेत अन्य मदों पर खर्च किया जाना होता है। इसके आलावा टेलीफोन बिल और बिजली बिल भी इसीमें शामिल है। साल भर का 5 हजार का तो टेलीफोन बिल ही हो जाता है। ऐसे में अन्य मदों के लिए बजट ही नही मिलता है। इसके लिए कई बार तो स्कूल स्टाफ ही पैसे एकत्रित कर अन्य मदों के पैसे देता है।

इनका कहना है

जिले में 390 स्कूल बिजली की समस्या से जूझ रहे है। हाल ही में 120 स्कूलों के लिए वार्षिक प्लान तैयार कर विभाग को भेजा है। एकाध साल में सभी स्कूलों बिजली पहुंचा दी जाएगी।

- नरपत सिंह हाडा, एईएन, सर्व शिक्षा अभियान, कोटा

Bhaskar News Group

Education भास्कर

अपॉर्च्युनिटी अपडेट

कक्षा 1 से 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए

इंटरनेशनल ओलिम्पियाड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 2018

किसके लिए : कक्षा एक से 12 तक के वे स्टूडेंट्स इसमें शामिल हो सकते हैं जिनकी इंग्लिश भाषा में रुचि हो। इसमें दो कैटेगरी हैं। कक्षा पहली व दूसरी के लिए 40 प्रश्न व कक्षा 3 से 12 तक के स्टूडेंट्स को 50 प्रश्न हल करने के लिए 60 मिनट दिए जाएंगे।

योग्यता : किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल में पहली से 12वीं कक्षा तक पढ़ने वाले सभी भारतीय स्टूडेंट्स आवेदन कर सकते हैं।

क्या मिलेगा : विजेताओं के तीन स्तर होंगे जिनमें स्टूडेंट्स को उनकी रैंक के आधार पर नगद व अन्य तरह के इनाम प्राप्त होंगे।

आवेदन की अंतिम तिथि : 31 अगस्त, 2018

http://www.b4s.in/DBL/IOO15

हमिंग बर्ड मैथेमेटिक्स ओलिम्पियाड (एचएमओ) 2018

किसके लिए : कक्षा 1 से 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए यह मैथेमेटिक्स ओलिम्पियाड है। इसमें मल्टीपल च्वॉइस क्वेश्चन पैटर्न के आधार पर 50 मिनट में प्रश्न पत्र हल करना होगा, जिसके तहत विद्यार्थियों को कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल, लॉजिकल, रीज़निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और एनालिटिकल स्किल को बढ़ाने व मजबूत बनाने का अवसर प्राप्त होगा। यह ओलिम्पियाड तीन भाषाओं- इंग्लिश, हिंदी व तमिल में से किसी में दे सकते हैं।

योग्यता : सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड या अन्य किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पहली से 12वीं कक्षा की शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं।

क्या मिलेगा : राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य, व विद्यालयीन स्तर पर चयनित विजेताओं को अलग-अलग इनाम मिलेंगे।

आवेदन की अंतिम तिथि : 31 अगस्त, 2018

http://www.b4s.in/DBL/HBM1

'2018 Doodle 4 Google'

किसके लिए : गूगल ने देश भर के कला प्रेमी छात्रों को अपनी कल्पनाशीलता का परिचय देने के लिए 2018 Doodle 4 Google' प्रतियोगिता की घोषणा की है। इसमें गूगल के डूडल में आकार देने का मौका मिलेगा। जीतने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इस साल की थीम है 'आपको क्या प्रेरित करता है।' इसमें डूडल में शामिल अक्षरों (GOOGLE) को क्रेयॉन्स, क्ले, वॉटर कलर्स, ग्राफिक डिजाइन से कुछ भी क्रिएटिव करके सजाना है।

योग्यता : कक्षा 1 से 10 तक के स्टूडेंट्स इसमें शामिल हो सकते हैं।

क्या मिलेगा : पांच लाख रुपए का इनाम। जीतने वाले डूडल को गूगल के होमपेज पर बाल दिवस के अवसर पर प्रदर्शित किया जाएगा।

अंतिम तिथि : 6 अक्टूबर

www.google.com/doodles

18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए

एफआईसीए इमर्जिंग आर्टिस्ट अवॉर्ड 2018

किसके लिए : भारतीय युवा कलाकार जो विज़ुअल आर्ट के क्षेत्र में विशेष कौशल रखते हों व विदेश में रहकर कार्य करने का अवसर प्राप्त करना चाहते हों वे स्विस आर्ट काउंसिल व फाउंडेशन फॉर इंडियन कंटेम्पररी आर्ट द्वारा आयोजित इस अवॉर्ड में भाग ले सकते हैं। इसके तहत उम्मीदवारों को नई दिल्ली में अपने कार्य का प्रदर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा।

योग्यता : विज़ुअल आर्ट में विशेष कौशल हो तथा आयु 18 से 35 वर्ष के बीच हो।

क्या मिलेगा : स्विट्ज़रलैंड में 90 दिन के स्टे सहित हवाई यात्रा किराया, प्रतिदिन का खर्च व एफआईसीए 2020 की वार्षिक प्रदर्शनी में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा।

आवेदन की अंतिम तिथि : 31 अगस्त, 2018

http://www.b4s.in/DBL/FEA3

साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2019

किसके लिए : भारतीय युवा प्रकाशक व लेखकों से साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित इस पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। यह अवॉर्ड अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त सभी 24 भाषाओं के लिए है। अतः प्रतिभागी इन्हीं 24 भाषाओं में से ही किसी भी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। इस अवॉर्ड का उद्देश्य लेखकों को भारतीय भाषाओं में लिखने के लिए प्रोत्साहित करना है।

योग्यता : सभी भारतीय युवा लेखक जिनकी आयु 1 जनवरी 2019 को 35 वर्ष से अधिक न हो।

क्या मिलेगा : 50,000 रुपए का नगद इनाम प्राप्त होगा।

आवेदन की अंतिम तिथि : 20 अगस्त, 2018

http://www.b4s.in/DBL/SAY1

न्यूज़ ट्रेंड

अब भर्तियों में तेजी आने की संभावना

70 %
रिक्रूटर्स का मानना है कि अब दिसंबर तक भर्तियों में तेजी आएगी और नौकरियों से छंटनी नगण्य रह जाएगी।

2 %
रिक्रूटर्स का मानना है कि नौकरियों में छंटनी जारी रह सकती है।

55%
कंपनियों का मानना है कि अगले अप्रेज़ल सेशन में उद्योग अपने कर्मचारियों के वेतन-भत्ते 10 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ाएंगे।

20%
का मानना है कि इन्क्रीमेंट में 10 से 20% की वृद्धि कर्मचारियों की उपलब्धियों के आधार पर होगी।

इन क्षेत्रों में बढ़ेंगे रोज़गार : स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, डाटा माइनिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग।

(स्रोत : नौकरी हायरिंग आउटलुक सर्वे)

सवाल और सुझाव के लिए एसएमएस कीजिए... 9200012345 पर या ई-मेल कीजिए
education@dbcorp.in

सीईओ स्पष्टीकरण दें क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए : कोर्ट

जयपुर | हाईकोर्ट ने एलडीसी भर्ती पंचायत राज- 2013 के मामले में जिला परिषद सवाई माधोपुर के सीईओ को अवमानना का दोषी मानते हुए उन्हें कहा है कि वे 24 अगस्त को अदालत में हाजिर होकर बताएं कि उन्होंने अदालती आदेश का पालन क्यों नहीं किया। साथ ही उन्हें 4 अगस्त 2017 को दिए आदेश की पालना नहीं करने पर अवमानना की कार्रवाई से दंडित किया जाए। अदालत ने यह अंतरिम निर्देश अनिता जैन की अवमानना याचिका पर दिया। मामले के अनुसार, 2013 की एलडीसी भर्ती में प्रार्थिया अनीता जैन ने वर्ष 2017 में प्रसूति अवकाश व मेडिकल अवकाश के समय को अनुभव प्रमाण पत्र में शामिल करने की याचिका दायर की थी। अदालत ने याचिका मंजूर कर उसे दोनों अवकाश स्वीकृत कर अनुभव प्रमाण पत्र देने के लिए शामिल करने का निर्देश दिया था।

आरएएस प्री 2018 : आंसर की पर आज रात 12 बजे तक दी जा सकेगी आपत्ति

अजमेर | राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित आरएएस प्री 2018 की आंसर की पर बुधवार रात 12 बजे तक ऑनलाइन आपत्तियां दी जा सकेंगी। आयोग का सर्वर डाउन होने पर कई अभ्यर्थियों को हुई परेशानी को देखते हुए अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए यह तिथि बढ़ाई गई है। पूर्व में अंतिम तिथि 13 अगस्त तक तय की गई थी। आयोग उपसचिव रामदयाल मीणा के अनुसार अब आपत्तियां देने के लिए 15 अगस्त 2018 को रात 12 बजे तक आपत्तियां दर्ज कराने के लिए लिंक खोला गया है, ताकि अभ्यर्थी ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकें।

4 विश्वविद्यालयों में 8 भर्तियां निकली, सभी पर विवाद, अटकीं

- 151 पदों पर हो रही हैं यह भर्तियां, 6 पर राज्यपाल और कोर्ट ने लगाई रोक
- एक भर्ती कोर्ट में लंबित, मामला उलझा तो एक भर्ती खुद विवि ने स्थगित की
- विश्वविद्यालयों में 40 फीसदी पद खाली, अब स्वायत्त आयोग की मांग

मोहर सिंह मीणा | जयपुर

प्रदेश के चार बड़े सरकारी विश्वविद्यालयों में पिछले दिनों 8 भर्तियां निकाली गई। यह सभी भर्तियां विवादों के कारण अटक गई। विवाद इतना बढ़ गया कि इनमें से 6 भर्तियों पर या तो राज्यपाल को रोक लगानी पड़ी या कोर्ट को। शेष दो भर्तियों में एक अभी कोर्ट में लंबित है तो दूसरी को यूजीसी नियमों के दरकिनार कर निकाले गए विज्ञापन के कारण विश्वविद्यालय प्रबंधन ने खुद ही स्थगित कर दिया। उच्च शिक्षा में इस प्रकार भर्तियां अटकने से सवाल खड़े हो रहे हैं। इन विश्वविद्यालयों में पढ़ाई कर रहे लाखों विद्यार्थी शिक्षकों का इंतजार कर रहे हैं। भर्तियां अटकने से अब उनकी पढ़ाई बाधित होने की स्थिति भी बन गई है। शिक्षाविदों का कहना है कि विवि में भर्तियों के लिए अगर एक आयोग का गठन कर दिया जाए तो विवादों से बचा जा सकता है।

एक्सपर्ट व्यू

विवि में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। नियुक्तियों में पारदर्शिता होनी चाहिए यानी चयनित अभ्यर्थियों का बायोडाटा विवि की वेबसाइट पर उपलब्ध होना चाहिए। विवि की भर्तियों के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरह स्वायत्त आयोग होना चाहिए। सलेक्शन कमेटी में सरकार के प्रतिनिधि राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रख्यात शिक्षाविद् होने चाहिए जिससे भर्तियों की विश्वसनीयता बनी रहे।

-प्रो. नवीन माथुर

जानिए विश्वविद्यालयों में भर्तियों पर विवाद की छाया क्यों?

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

नियमों का उल्लंघन, राज्यपाल और कोर्ट ने लगाई रोक

यहां डिप्टी रजिस्ट्रार के 5 पदों पर भर्ती निकाली गई। भर्ती परीक्षा की मेरिट में नहीं आने वालों को भी साक्षात्कार में बुला लिया गया। एक अभ्यर्थी पर फर्जी पे स्लिप देने का मामला और एक पर एसीबी में भ्रष्टाचार के आरोप में एफआईआर दर्ज होने के बावजूद दोनों का चयन कर लिया गया। विवाद बढ़ा तो राज्यपाल ने चयनितों को जॉइन नहीं कराने और भर्ती प्रक्रिया को रोकने के आदेश दिए। इसी प्रकार यहां 7 पदों पर फिजिक्स असिस्टेंट प्रोफेसर और 5 पदों पर केमिस्ट्री असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकाली गई। दोनों ही भर्तियों में कोर्ट के आदेश के बावजूद अभ्यर्थी को साक्षात्कार में शामिल नहीं करने का मामला सामने आया। कोर्ट ने चयनितों के नाम के लिफाफे खोलने पर भी रोक लगाई थी लेकिन लिफाफे खोल लिए गए। नतीजा यह रहा कि राज्यपाल को भर्ती पर रोक लगानी पड़ी। एक पद पर एबीएसटी एसोसिएट प्रोफेसर भर्ती निकाली गई, लेकिन यूजीसी के नियमानुसार वेतनमान नहीं होने के बावजूद कुछ अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया गया। इससे नाराज एक अभ्यर्थी कोर्ट चला गया और कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी।

जोधपुर का जयनारायण व्यास विवि

असि. प्रोफेसर के 111 पद, विवि ने ही योग्यता नियमों को भुला दिया

यहां असिस्टेंट प्रोफेसर के 111 पदों पर भर्ती निकाली गई। इस भर्ती में नियुक्ति के लिए अयोग्य सहायक आचार्यों को भी जॉइन करा लिया गया। विश्वविद्यालय ने विज्ञापन में शैक्षणिक योग्यता के नियमों की अनदेखी की। 7 असिस्टेंट प्रोफेसर की योग्यता आवेदन की अंतिम तिथि तक पूर्ण नहीं थी, वहीं 26 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्ति ऑर्डिनेंस के अनुरूप नहीं थी। इस मामले पर राज्य सरकार ने जांच कमेटी बनाई। जिसने भर्तियां रद्द करने की सिफारिश की थी। मामला अब कोर्ट में लंबित है।

कोटा विश्वविद्यालय

भर्ती में राजनीतिक रसूख चला, विवाद

यहां असिस्टेंट रजिस्ट्रार के चार पदों पर भर्ती निकाली गई। इसमें चयनित चार में से एक उम्मीदवार के 1 साल के पीजी डिप्लोमा को ही पीजी मान लिया था, जबकि अन्य 3 राजनैतिक रसूखदारों के परिचित थे। मामला बढ़ा तो जांच हुई लेकिन विवादों के बीच इनको जॉइनिंग भी दे दी गई।

उदयपुर का सुखाड़िया विवि

मापदंडों की अनदेखी, परीक्षा में सवाल गलत...जवाब 'सही'

यहां बायोटेक्नोलॉजी के एक पद पर प्रोफेसर भर्ती निकाली गई। बायोटेक्नोलॉजी विभाग में प्रोफेसर के पद पर डॉ. राजेश कुमार दुबे की नियुक्ति की गई है। इस नियुक्ति के संबंध में शिकायतें थी कि दुबे का ए.पी.आई. स्कोर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मापदंडों से कम है। साथ ही पूर्व में दुबे जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर में स्थापित एचआरडीसी में निदेशक पद पर कार्यरत थे। यहां से इनको अनापत्ति प्रमाणपत्र के अभाव, बिना इस्तीफे व रिलीव हुए बगैर सुखाड़िया विश्वविद्यालय में कार्यग्रहण भी करवा लिया गया था। मामला बढ़ा तो राज्यपाल ने लोकायुक्त से जांच कराने के आदेश दिए हैं। इस विवि में 15 पदों पर हुई एलडीसी भर्ती परीक्षा में 75 में से 18 प्रश्न गलत होने के बावजूद एक अभ्यर्थी के 75 में से 75 प्रश्न 'ठीक' थे। भर्ती विवादों में आई। खास बात यह है कि वह अभ्यर्थी विवि के कुलपति के गांव का ही रहने वाला था। राज्यपाल ने भर्ती को स्थगित कर दिया था। इसी प्रकार यहां डिप्टी रजिस्ट्रार के दो पदों पर भर्ती निकाली गई। इसमें यूजीसी के नियमानुसार योग्यता निर्धारित नहीं की गई थी इसलिए इस पर विवाद बढ़ा तो इस भर्ती विज्ञापन को स्थगित किया गया था।

इस बार जेएनवीयू रीवैल्यूएशन के परिणाम पूरक परीक्षाओं से पहले आएंगे, 30 तक का लक्ष्य

एजुकेशन रिपोर्टर | जोधपुर

जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी ने स्थापना से लेकर अब तक में पहली बार जल्दी परिणाम घोषित करने का रिकॉर्ड बनाया है। इस बार अधिकांश परीक्षाओं के परिणाम शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले ही घोषित कर दिए गए। अब यूनिवर्सिटी की ओर से 30 अगस्त तक सभी रिवैल्यूएशन के परिणाम घोषित करने की तैयारी चल रही है। जिससे रिवैल्यूएशन में उत्तीर्ण हो जाने वाले स्टूडेंट्स को पूरक परीक्षाएं देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जेएनवीयू की ओर से हर वर्ष आयोजित परीक्षाओं के परिणाम अगस्त अंतिम सप्ताह तक घोषित होते, इसके बाद ग्रेजुएशन फाइनल इयर की पूरक परीक्षाएं घोषित होने तक रिवैल्यूएशन के परिणाम भी घोषित नहीं हो पाते तथा रिवैल्यूएशन के परिणाम आने तक आधा सत्र निकल जाता। इन सबके चलते आधा सत्र निकलने तक स्टूडेंट को यह पता नहीं चल पाता कि उसे इस बार किस वर्ष अथवा सेमेस्टर की परीक्षा देनी है। इस बार जेएनवीयू की व्यवस्थाओं में बड़ा बदलाव हुआ, जिससे जुलाई के पहले सप्ताह तक अधिकांश परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए। विश्वविद्यालय की ओर से अब रिवैल्यूएशन के परिणाम भी घोषित करने की तैयारी है। विवि की गोपनीय शाखा व परीक्षा शाखा की ओर से इस बार परिणाम अगस्त के आखिरी सप्ताह तक घोषित करने की तैयारी है।

क्या होगा फायदा

- जिन यूजी स्टूडेंट्स के फाइनल की परीक्षा में पूरक आई है, समय पर रिवैल्यूएशन परिणाम में उत्तीर्ण होने पर पूरक परीक्षा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
- जिन पीजी प्रीवियस स्टूडेंट्स का परिणाम अनुत्तीर्ण रहा है, समय पर परिणाम आने पर फाइनल ईयर की परीक्षाओं की तैयारी आसानी से शुरू कर सकेंगे।
- यूजी में जिनके ड्यू आई है, परिणाम में उत्तीर्ण होने पर अगली कक्षा की परीक्षाओं की तैयारी आसानी से शुरू कर सकेंगे।

चार साल के लिए आए थे, बिना स्वीकृति के 10 साल से जमे हैं यूआईटी में

कोटा | शहर में यूआईटी में करोड़ों के निर्माण कार्यों को देखते हुए दूसरे विभागों के इंजीनियर्स यहां आने के लिए लालायित रहते हैं। वे जोड़-तोड़कर यहां आते हैं और फिर वर्षों तक यहां टिके रहते हैं।

सचिव बोले-अब इंजीनियर्स की नियुक्ति की जांच करवाएंगे

हालत यह है कि तीन इंजीनियर्स तो जेईएन के रूप में आए थे, यहीं पर एईएन बने और अब यूआईटी में ही मर्ज होने की तैयारी में हैं। इसके अलावा दूसरे विभागों से भी इंजीनियर्स यहां आ रहे हैं, जिसके कारण यहां के इंजीनियर्स की वरिष्ठता प्रभावित हो रही है। इस बारे में जब सचिव आनंदीलाल वैष्णव से बात की तो उन्होंने भी माना कि यह तो सही है कि कुछ इंजीनियर्स यहां पर लंबे समय से जमे हुए हैं, अब इनके आदेशों की जांच करवाई जाएगी।

चार साल के लिए होता है डेपुटेशनः

यूआईटी की स्थापना शाखा के अनुसार डेपुटेशन 4 साल के लिए होता है, इससे अधिक के लिए वित्त विभाग से फिर से स्वीकृति लानी होती है। तीन इंजीनियर आरएस गुप्ता, शिवभूषण शर्मा तथा कमल मीणा बिना चार साल से ज्यादा समय से ड्यूटी दे रहे हैं। स्थापना शाखा के अनुसार इन तीनों इंजीनियर्स के चार साल के बाद से कोई स्वीकृति लेटर विभाग के पास नहीं है, जबकि उनको यूआईटी में करीब दस साल हो गए हैं। वहीं, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए इंजीनियर्स को डेपुटेशन पर मंगा जा रहा है, लेकिन कोई जाने के लिए तैयार नहीं है।

शिक्षा का सच | आजादी के पहले से संचालित किशोरपुरा स्कूल किराए के भवन में चल रहा

एक बच्चे पर सालाना 28 हजार 560 रुपए खर्च करती है सरकार, फिर भी पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं

स्कूल बनाने के लिए जमीन नहीं, 20 लाख का रुपए का बजट जारी

सिटी रिपोर्टर | कोटा

एजुकेशन पर सरकार एक स्टूडेंट्स पर हर साल 28 हजार 560 रुपए खर्च कर रही है, लेकिन शहर का आजादी से पहले से संचालित किशोरपुरा सेकंडरी स्कूल में आज भी स्टूडेंट्स पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं।

इस स्कूल की जमीन आवंटन को लेकर शिक्षा विभाग से लेकर स्कूल प्रशासन की ओर से सांसद से लेकर विधायक, यूआईटी और निगम की ओर से कई बार पत्र लिखे जा चुके हैं, लेकिन समाधान तक नहीं निकल पाया है। राज्य सरकार ने इस सेशन से बगैर जमीन दिए ही मिडिल से सेकंडरी में क्रमोन्नत हो गया है। जबकि यह स्कूल शुरुआत से ही जेठियों के अखाड़े में किराए से संचालित है। बच्चे बरामदों से लेकर तिबारियों में पढ़ते हैं। बच्चों को बिजली की सुविधा तक नहीं है। सबसे बड़ी हास्यास्पद बात है कि राज्य सरकार की और से इस स्कूल

में कमरों के लिए 20 लाख 10 हजार रुपए का बजट स्वीकृत जारी कर दिया है। चिंता हैं कि अब यह बजट जमीन नहीं मिलने से उपयोग नहीं आएगा।

हो चुका है जमीन का भूमि पूजन, शिलापट है गवाही

किशोरपुरा स्कूल में 2006 में तत्कालीन संसदीय सचिव ओम बिरला द्वारा 2006 में भूमि पूजन की शिलापट्ट आज भी गवाह है। उस समय इस स्कूल के लिए जमीन का आवंटन किया गया था। लेकिन जमीन विवादित होने के कारण यह भवन अभी तक नहीं बन सका है।

यह है नामांकन

कक्षा	नामांकन
1	15
2	14
3	19
4	24
5	20
6	30
7	35
8	23
9	32

क्रमोन्नत से नामांकन बढ़ा, लेकिन बैठने के लिए जगह नहीं है

स्कूल में पहले 450 स्टूडेंट्स का नामांकन था। यहां दो पालियों में स्कूल संचालित होता था। लेकिन यहां भवन की सुविधा नहीं मिलने से परेशानी हो रही है। यहां क्रमोन्नत होने के बाद अब नामांकन बढ़ने लगा है। लेकिन, यहां अब जगह नहीं होने और किराए का भवन होने से समस्या हो गई है।

अधिकारी बने हैं स्कूल से, बनी थी पैठ

पूर्व एडीईओ नरेंद्र गहलोत ने बताया कि इस स्कूल में वो स्वयं के अलावा उनके भाई के अलावा यूआईटी सचिव तक बने हैं। लेकिन, आजादी से पहले इस स्कूल को भवन के लिए जमीन तक नहीं मिली है।

सरकार का माध्यमिक शिक्षा के प्रति स्टूडेंट्स पर खर्च

वर्ष	खर्च
2015-16	19117
2016-17	24756
2017-18	28560

किशोरपुरा स्कूल को क्रमोन्नत किया है। इसके लिए 20 लाख 10 हजार का बजट जारी किया है। लेकिन, इसकी जमीन नहीं है। रमसा के अनुसार ऐसे में बजट का उपयोग नहीं किया हो सकता है। **संजय मीना, एपीसी रमसा**

स्कूल की जमीन को लेकर कई बार प्रयास किए। इस इलाके में बच्चों की सुविधाजनक जमीन नहीं मिल पा रही है। 16 अगस्त को इस संबंध में कलेक्टर गौरव गोयल से बातचीत की समाधान के प्रयास करेंगे। - **संदीप शर्मा, विधायक**

इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में अलग-अलग कॉलम में भरनी होगी ब्याज राशि

कोटा | इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म में विभाग की ओर से बदलाव किए गए हैं। इसके अंतर्गत रिटर्न भरने वाले को अपने सेविंग एकाउंट, एफडीआर और रिफंड पर मिलने वाले ब्याज को अलग-अलग कॉलम में भर कर देना होगा।

हाल ही में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की कोशिश करने वाले सैलरी टैक्सपेयर को बदलाव देखने को मिले हैं। टैक्सपेयर को बैंक सेविंग अकाउंट्स से ब्याज, टर्म डिपॉजिट, इनकम टैक्स रिफंड पर ब्याज और दूसरे ब्याज को अलग अलग दिखाने को कहा जा रहा है। बैंक खातों से मिले ब्याज की जानकारी आसानी से मिल जाती है, लेकिन कई लोग आईटी रिफंड पर ब्याज की जानकारी नहीं दे रहे थे। इसी तरह कॉर्पोरेट एंट्रीज के इस्तेमाल वाले आईटीआर-7 सहित सभी फॉर्म में कई बदलाव किए जा चुके हैं।

विदेश में एमबीबीएस

वर्ष 2018 से भारतीय चिकित्सा परिषद् (MCI) ने देश या विदेश से MBBS करने के लिए NEET उत्तीर्ण करना आवश्यक कर दिया है,

चीन में कुल 259 मेडिकल युनिवर्सिटी हैं तथा सभी सरकारी है। सभी युनिवर्सिटी में MBBS की पढाई अंग्रेजी माध्यम में MCI पैटर्न पर होती है तथा सभी की इंटरनशीप भारत में मान्य है क्योंक यहां क्लिनीकल पढाई तथा क्लीनीकल एक्सपेरिमेंट के लिए अत्याधुनिक लैब, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल/ हॉस्पिटल हैं, जहां विद्यार्थी को डेड बॉडी डाइसेक्सन के लिए मिलता है। चीन में काफी मरीज OPD तथा IPD में इलाज के लिए आते हैं जिससे विद्यार्थी की क्लीनिकल पढाई अच्छी हो जाती है।

चीन में कई Famous University हैं जो काफी लम्बे समय से स्थापित हैं MCI Coaching अच्छे प्रोफेसर के द्वारा तैयारी करवाई जाती है जिससे छात्रों को पढाई करने में आसानी रहती है।

चीन में राजस्थानी कुक व शाकाहारी भोजन मिलता है। लड़के व लड़कियों के लिए अलग छात्रावास की व्यवस्था है यहां मौसम देहरादून, शिमला जैसा रहता है तथा बर्फ नहीं गिरती है। चीन के लोग भगवान बुद्ध की पूजा करते है। भगवान बुद्ध भारत में पैदा हुए है इसलिए भारत के विद्यार्थियों को काफी सम्मान देते है।

राजस्थान प्रशासनिक सेवा

राजस्थान की सिविल सेवा भर्ती परीक्षा है। आरपीएससी द्वारा आयोजित ये परीक्षा सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा हैं। हर साल कई छात्र इस परीक्षा में शामिल होते हैं और एग्जाम पास करके सरकारी क्षेत्र में अपना करियर बनाते हैं।

आरएएस राजस्थान के राज्य में सबसे प्रतिष्ठित सरकारी नौकरियों के लिए केंद्रीय भर्ती परीक्षा है। इस परीक्षा में सफल छात्र सरकारी क्षेत्र के विभागों के विभिन्न पद जैसे उप सचिव, संयुक्त सचिव, उपायुक्त, विशेष सचिव, विभाग के प्रमुख, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रमुख सचिव और मुख्य सचिव सभी आरएस समिति के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

जीपीएस वाहन सुरक्षा

आज जीपीएस Technology का उपयोग आम जीवन में बहुत तेजी से बढ़ रहा है जहां जीपीएस सुरक्षा की दृष्टि से बेहतरीन साबित हो रही है अपराधिक गति विधियों पर नियंत्रण, वाहनों की ट्रेकिंग, मोबाइल फोन नेविगेशन, एमरजैंसी सर्विसेज में इसका उपयोग हो रहा है। जीपीएस वाहन सुरक्षा का बेहतरीन तरीका है इस तकनीक की सहायता से कई वाहन चोरी होने से बचे हैं व वाहन चोर पकड़े गये है सरकारी विभागों में भी इस तकनीक का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है।

चार पदों पर चयनित 203 अभ्यर्थियों के दस्तावेज का सत्यापन 18 व 19 अगस्त को

सिटी रिपोर्टर | जोधपुर

चुनावी साल में सरकारी विभागों में बंपर भर्तियां हो रही हैं। प्रदेश की पांचों बिजली कंपनियों के लिए लंबे समय बाद 4417 पदों के लिए भर्ती होने जा रही है। इन पदों के लिए 2.61 लाख बेरोजगारों ने आवेदन किया है। इसमें राजस्थान सहित देश भर से आवेदन मांगे गए थे। नोन टेक्निकल श्रेणी के छह अलग-अलग पदों के लिए ऑनलाइन परीक्षा हो चुकी है। इसके लिए राजस्थान सहित बाहरी राज्यों में 80 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। आगामी 18 व 19 अगस्त को जोधपुर डिस्कॉम व अन्य कंपनियों में 42 अकाउंट ऑफिसर, 27 पर्सनल ऑफिसर, 67 असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर तथा 67 जूनियर लीगल असिस्टेंट के दस्तावेज की जांच होगी। इसके बाद सितंबर के पहले सप्ताह में नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे।

23 अगस्त को ईद-उल-जुहा, केंद्र के दफ्तरों में छुट्टी

नई दिल्ली | केंद्र सरकार ने 23 अगस्त, गुरुवार को ईद-उल-जुहा के मौके पर अपने दिल्ली स्थित सभी सरकारी दफ्तरों में छुट्टी रखने की घोषणा की है। इससे पहले यह छुट्टी 22 अगस्त को तय थी। इस बारे में केंद्रीय कार्मिक विभाग की ओर से मंगलवार को एक आधिकारिक बयान भी जारी किया है।

12वीं के बाद लॉ एंड जुडिश्यरी में कैरियर

फील्ड चाहे कोई भी क्यों न हो जब तक मनोवांच्छित सफलता नहीं मिलती है तब तक उस फील्ड को चुनने के मायने नहीं। यह बात लॉ एण्ड जुडिशिरी के क्षेत्र में भी लागू होती है। इस विषय का विश्लेषण करने से पहले यह जानना जरूरी है कि भविष्य की सम्भावनाएं क्या है? यह वह दौर है जब वर्तमान में भारत और संपूर्ण विश्व में लॉ को कैरियर के रूप में सर्वाधिक अच्छा समझा जा रहा है। संपूर्ण देश और उसकी हर व्यवस्था कानून के साथ अटूट रूप से बंधी हुई है। इस बात पर भी मंथन हो रहा है कि लॉ को क्यों न अनिवार्य शिक्षा के रूप में प्रतिष्ठित किया जाये...

न्यायाधीशो की सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण समाज का हर वर्ग अपने बच्चों को लॉ एण्ड जुडिशियरी में चाहता है। लॉ कोर्स करने के बाद भविष्य में कोई विद्यार्थी न्यायिक मजिस्ट्रेट, जुडिशियल ऑफिसर, टैक्स ट्रिब्यूनल न्यायधीश, उच्च एवं उच्चतम् न्यायालय में न्यायाधीश तक बन सकता है। यदि स्वयं की प्राईवेट प्रैक्टिस लॉ सेक्टर में करना चाहता है तो सेशन कोर्ट, हाईकोर्ट, टैक्स ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स आदि हर स्थान पर प्रैक्टिस कर सकता है।

भविष्य की संभावनाएं-

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लॉ का स्वरूप कुछ सामान्य भिन्नताओं को छोड़कर एक समान है। लॉ ग्रेजुएट अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लीगल कंसल्टेंसी दे सकता है। भारत के कुछ एडवोकेट्स अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी सेवायें देते है। हर कम्पनी अपने पैनल लॉयर्स रखती है। सरकार के प्रत्येक विभाग में लॉ एडवाइजर्स की आवश्यकता होती है, अधिकतर बड़ी संस्थाएं अपने यहां एडवोकेट्स और लीगल कंसल्टेंट्स की सेवायें लेती है।

प्रत्येक पुलिस थाने का एक अभियोजन अधिकारी होता है जो सरकार की ओर से कोर्ट में पैरवी करता है। उपरोक्त सभी क्षेत्रों के लिए उच्च गुणवत्तायुक्त अध्ययन और अध्यापन की आवश्यकता है इसलिये लॉ कालेज और यूनीवर्सिटीज में प्रोफेसर्स की डिमाण्ड बहुत ज्यादा है।

BCI ने 12वीं और ग्रेजुएशन के बाद लॉ कोर्स को मान्यता दी है। 12वीं के बाद साइन्स, कॉमर्स, आर्टस स्टूडेण्ट्स इस कोर्स में एडमिशन ले सकते है। BA, LLB एवं BBA, LLB पांच वर्षीय कोर्स में राजस्थली जुडिशियल स्कूल (विवेकानंद ग्लोबल विश्वविद्यालय) में प्रवेश प्राप्त कर सकते है। इस कोर्स में विद्यार्थियों को प्रथम वर्ष से ही न्यायिक सेवाओं के लिये तैयार कराया जाता है। 5 वर्ष बाद जब छात्र निकलता है तब उसे किसी कोचिंग संस्थान में अपने जीवन के बहुमूल्य 2 से 3 वर्ष प्रतियोगिता परीक्षा में देने से बच जाते है और पांच वर्षीय लॉ कोर्स की तैयारी में उसे पता भी नहीं चलता है कि कॉम्पीटीशन की तैयारी कब पूरी हो गयी।

वर्तमान समय में न्यायिक सेवाओं में सफल विद्यार्थी 26 से 32 वर्ष औसत आयुवर्ग के है, इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थली ने लगभग 23 वर्ष की आयु में न्यायिक मजिस्ट्रेट तैयार करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की है। यह भारतवर्ष का प्रथम जुडिशियल स्कूल ऑफ लॉ है। राजस्थली के न्यायिक सेवा में 100 से ज्यादा मजिस्ट्रेट, 19 जिला न्यायाधीश, 89 लोक अभियोजक, 20 जूनियर लॉ ऑफिसर्स कार्य कर रहे है।

जब टार्गेट ज्यूडिश्यरी है, तो क्लैट की तैयारी क्यों?

भारत सरकार ने उदारीकरण की नीति 1991 मे अपनायी थी तब प्राईवेट सेक्टर और कारपोरेट सेक्टर की यह मांग थी कि लॉ के ऐसे विद्यार्थियों को तैयार किया जाये जो कारपोरेट सेक्टर को भारतीय कानूनों की जानकारी दे सके और उनके उपचारों तथा उनकी पैरवी करने के तरीके बता सके एवं इसका कोर्स भी इसी रूप में डिजाइन किया गया था।

यह भ्रम उत्पन्न हो गया है कि NLU में प्रवेश लेने से न्यायिक अधिकारी बन जायेंगे, जबकि राजस्थान न्यायिक सेवा में वर्तमान में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज से आने वाले न्यायिक अधिकारी नाममात्र के है, क्योंकि NLU का पाठ्यक्रम न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के पाठ्यक्रम से मैच नहीं करता है।

वर्तमान में न्यायिक सेवा एवं सुविधाएं

वर्तमान समय में न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी अन्य प्रतियोगिता परीक्षा जैसे IAS, RAS की तुलना में कम प्रतिस्पर्धात्मक है। इसका पाठ्यक्रम भी अपेक्षाकृत लघु एवं सारगर्भित है जबकि सुविधाओं की दृष्टि से अन्य सेवाओं से बहुत अग्रणी है। समाज में भी न्यायिक सेवा ज्यादा प्रतिष्ठावान है। सरकारी हस्तक्षेप इस सेवा में बिल्कुल भी नहीं है।

प्रशासनिक सेवा में लॉ का महत्व

वर्तमान समय में IAS एवं RAS की प्रतियोगिता परीक्षा के सिलेबस में लॉ को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल कर लिया गया है। जो विद्यार्थी प्रशासनिक सेवाओं में जाने की सोच रहे है। उन्हें BA, LLB व BBA, LLB कोर्स करना चाहिए क्योंकि प्रशासनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा का कोर्स साथ ही तैयार हो जाता है। एम.के. सिंह

स्वतंत्रता समारोह में आज दो कलेक्टर सहित 19 कार्मिक होंगे सम्मानित

भास्कर न्यूज | जयपुर

15 अगस्त को राज्यस्तरीय कार्यक्रम में कलेक्टर करौली अभिमन्यु कुमार, कलेक्टर बांसवाड़ा भगवती प्रसाद सहित 19 कार्मिकों को एसएमएस स्टेडियम में सम्मानित किया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से सम्मानित किए जाने वाले कार्मिकों की लिस्ट जारी कर दी गई है। सूचना के अनुसार दो कलेक्टरों के अलावा उपसचिव वित्त दिनेश कुमार शर्मा, वरिष्ठ आचार्य न्यूरोसर्जरी एसएमएस डा.वीरेंद्र डी सिन्हा, अतिरिक्त निदेशक आईटी रमेश चंद शर्मा, अधीक्षण अभियंता सिविल सार्वजनिक निर्माण विभाग सुनील गुप्ता, सह आचार्य ईएनटी एसएमएस अस्पताल डा.मोहनीश ग्रोवर, निजी सचिव कार्मिक विभाग रमेश चंद कुमावत, संयुक्त निदेशक सांख्यिकी सीएमओ हरिओम प्रसाद शर्मा, होम्योपैथ चिकित्सा अधिकारी डा.तारा प्रसाद यादव, सहायक विधि परामर्शी सुनील कुमार गुप्ता, एसओ कार्मिक विभाग प्रमेंद्र शर्मा, सीईओ ग्रामीण विकास विभाग सुरेंद्र सिंह राठौड़ को अधिकारी वर्ग में सम्मानित किया जाएगा। राजेंद्र कल्ला, महेंद्र कुमार, रमेश कुमार शर्मा, देवेंद्र सिंह शेखावत, राजू बलाई, नरेंद्र सिंह सोलंकी को कर्मचारी वर्ग में पुरस्कृत किया जाएगा।

खजूरपुरा से तेल फैक्ट्री तक करीब होगा। कई लोग दुकानों से ही अपना करीब 3 से 4 साल का समय भी चेतावनी दी है। आईटी सिस्टम के संचालन के लिए

सख्ती अब भी लक्ष्य के मुकाबले कम हुए हैं नामांकन, अंतिम तिथि बढ़ाने की भी चल रही तैयारी

नामांकन का लक्ष्य पूरा नहीं किया तो संस्था प्रधानों पर कार्रवाई

भास्कर न्यूज | बारां

जिलेभर के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के नामांकन को लेकर प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में विभाग की ओर से निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अधिकारी, जनप्रतिनिधि, संस्था प्रधान, शिक्षक सभी जोर-शोर से नामांकन बढ़ाने के लिए जुटे हुए हैं। लेकिन अभी भी माध्यमिक शिक्षा के अधीन सरकारी स्कूलों का नामांकन लक्ष्य पूरा नहीं हो सका है।

लक्ष्य प्राप्ति को लेकर नामांकन की अंतिम तिथि बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में अब अंतिम तिथि तक लक्ष्य प्राप्त नहीं करने वाले संस्था प्रधानों को विभाग की ओर से कार्रवाई भी की जाएगी। प्रवेशोत्सव का प्रथम चरण 26 अप्रैल से 9 मई, दूसरा चरण 19 से 30 जून तक चला।

इस दौरान 1 हजार 563 विद्यार्थियों का नामांकन हुआ। फिर 15 जुलाई से 15 अगस्त तक बढ़ाई गई थी। लक्ष्य के मुकाबले नामांकन नहीं होने पर विभाग की ओर से अंतिम तारीख फिर बढ़ाई जाने की उम्मीद जताई जा रही है।

जिले में 285 स्कूल

जिले में माध्यमिक सेटअप के 285 स्कूल हैं। फिलहाल इनमें लक्ष्य के मुकाबले नामांकन का लक्ष्य पूरा नहीं हो सका हैं। इसको लेकर विभाग की ओर से प्रवेशोत्सव की अंतिम तिथि बढ़ाई थी। फिर तिथि बढ़ाने की तैयारी हो रही है। निदेशालय की ओर से जिले के माध्यमिक सेटअप के स्कूलों के पिछले साल के नामांकन 86 हजार 395 के मुकाबले 10 फीसदी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं, जो कि अभी पूरा नहीं हो सका है।

अभी यह है स्थिति : प्रथम चरण के प्रवेशोत्सव से लेकर वर्तमान तक 6 हजार 479 विद्यार्थियों का नामांकन हुआ है। इसमें 3536 छात्रों व 2943 छात्राओं का नामांकन हुआ है। जबकि निदेशालय से प्राप्त निर्देशानुसार जिले में माध्यमिक सेटअप के 285 स्कूलों में पिछले साल के नामांकन 86 हजार 395 के मुताबिक 8 हजार 639 विद्यार्थियों के अधिक नामांकन का लक्ष्य दिया है। ऐसे में अब विभाग की ओर से लक्ष्य पूरा नहीं करने वाले संस्था प्रधानों व शिक्षकों को विभाग की ओर से कार्रवाई की जाएगी।

स्कूलों में पिछले साल के नामांकन से 10 फीसदी अधिक विद्यार्थियों का नामांकन को लेकर निदेशालय से लक्ष्य मिला है। इसको लेकर अधिकारी, जनप्रतिनिधि व संस्था प्रधान जुटे हुए हैं। जिन स्कूलों का नामांकन लक्ष्य के मुताबिक 10 फीसदी नहीं बढ़ेगा। उन संस्था प्रधानों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

\- प्रहलाद राठौर, डीईओ (माध्यमिक)

तृतीय श्रेणी शिक्षक का लेवल दो से लेवल एक में ट्रांसफर के आदेश पर रोक

जयपुर | हाईकोर्ट ने प्रार्थी तृतीय श्रेणी शिक्षक का लेवल दो से लेवल एक में ट्रांसफर करने के 31 मई और रिलीविंग करने वाले 23 जून 2018 के आदेशों की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है। मामले में प्रमुख शिक्षा सचिव, डीईओ सवाई माधोपुर सहित तीन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायाधीश वीएस सिराधना ने यह अंतरिम निर्देश ललिता पाठक की याचिका पर दिया। याचिका में कहा कि जब एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर किया जाता है तो इससे प्रार्थी सीनियरिटी कम होती है। ऐसे में प्रार्थियों की सहमति लेना जरूरी था। इसलिए उसके ट्रांसफर व रिलीविंग आदेशों की क्रियान्विति पर रोक लगाई जाए।

राज्य के बाहर कार्यरत एनआरएचएम कार्मिकों को बोनस अंक का लाभ क्यों नहीं : कोर्ट

नर्स ग्रेड द्वितीय भर्ती-2018 का मामला

जयपुर | हाईकोर्ट ने नर्स ग्रेड द्वितीय भर्ती -2018 में राज्य के बाहर अन्य प्रदेशों में कार्यरत राज्य के निवासी एनआरएचएम कार्मिको को भर्ती में बोनस अंको का लाभ नहीं देने पर प्रमुख चिकित्सा सचिव, चिकित्सा निदेशक व अतिरिक्त चिकित्सा निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायाधीश वीएस सिराधना ने यह अंतरिम निर्देश तृप्ति पांडे की याचिका पर दिया। अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि प्रार्थिया राजस्थान प्रदेश की निवासी है और 2013 से मध्यप्रदेश की एनआरएचएम सेवा में कार्यरत है। राज्य सरकार ने नर्स ग्रेड द्वितीय भर्ती निकाली है जिसमें प्रदेश में काम कर रहे कार्मिकों को बोनस अंक का लाभ दिया जा रहा है। जबकि अन्य प्रदेशों में काम कर रहे कार्मिकों को बोनस अंक के लाभ से वंचित रखा जा रहा है। अदालत ने मामले में सुनवाई कर राज्य सरकार को जवाब देने के लिए कहा।

राज्य सरकार को जुर्माने की शर्त पर दिया दो सप्ताह का समय

ग्राम पंचायत सहायक भर्ती-2017 का मामला

तीगत रिपोर्टर | जयपुर

हाईकोर्ट ने पिछले साल प्रदेश में हुई ग्राम पंचायत सहायक के 27000 पदों की भर्ती में आरक्षण नहीं देने को चुनौती देने के मामले में राज्य सरकार द्वारा आदेश के बाद भी विस्तृत शपथ पत्र पेश नहीं करने पर सरकार पर 500 रुपए जुर्माना लगाते हुए दो सप्ताह का समय दिया है। न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व गोवर्धन बाढ़दार की खंडपीठ ने

यह अंतरिम निर्देश पेमाराम बैरवा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने शपथ पत्र पेश करने के लिए समय मांगा। जिस पर अदालत ने एक दिसंबर 2017 के आदेश पर अभी तक शपथ पत्र पेश नहीं करने पर नाराजगी जताई और समय देने से इंकार कर दिया। बाद में 500 रुपए जुर्माने की शर्त पर राज्य सरकार को दो सप्ताह का समय दिया। अधिवक्ता एसएल सोनगरा ने बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेश में 27000 ग्राम पंचायत सहायक के पदों पर नियुक्ति की थी लेकिन उसमें जानबूझकर आरक्षण का प्रावधान नहीं किया। इसलिए भर्ती में आरक्षण का प्रावधान भी लागू किया जाए।